



सत्यमेव जयते
Government of India

NCGG

National Centre for Good Governance
The Torch Bearers of Good Governance

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

“

उत्तम सुशासन महत्वपूर्ण है।
जन-केंद्रित शासन समस्याओं का समाधान करता है
और बेहतर परिणाम प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल 2023

स्वतंत्रता के अमृत काल में, हम एक पारदर्शी प्रणाली, कुशल प्रक्रिया और सुगम प्रशासन बनाने के लिए गतिशीलता से आगे बढ़ रहे हैं ताकि सार्वत्रिक और समग्र विकास हो सके।

- लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस भाषण, 15 अगस्त 2022

अच्छी शासन प्रबंधन की मूल भूमिका में निवास स्तर पर सेवा प्रदान है। अमृत काल में, हम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणाम और विकसित भारत की सृष्टि के प्रति हमारे प्रयासों में दृढ़ रहते हैं।

- लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस भाषण, 15 अगस्त 2021

श्री नरेंद्र मोदी
भारत के माननीय प्रधानमंत्री

”



वार्षिक रिपोर्ट २०२२-२३

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

अनुक्रमणिका

कार्यकारी सारांश	२
परिचय	३
न्यूनाचर्चित साल २०२२-२३ के दौरान एनसीजीजी की गतिविधियाँ	५
i.) क्षमता निर्माण कार्यक्रम	
ii.) राष्ट्रीय सुखम प्रशासन वेबिनार श्रृंखला	
iii.) प्रकाशन	
iv.) सहकारी परियोजनाएं	
v.) संस्थागत विकास	
एनसीजीजी खबरों में	२२
एनसीजीजी में प्रमुख वक्ता	२४
एनसीजीजी टीम	२८
अनुबंध I: परिशदीय निकाय के सदस्यों	३२
अनुबंध II: प्रबंध समिति के सदस्यों	३२
अनुबंध III: क्षमता निर्माण कार्यक्रम के विवरण मालदीव के सिविल सेवकों के लिए	३३
अनुबंध IV: क्षमता निर्माण कार्यक्रम के विवरण बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए	३३
अनुबंध V: क्षमता निर्माण कार्यक्रम के विवरण जम्मू और कश्मीर के सिविल सेवकों के लिए	३४
अनुबंध VI: क्षमता निर्माण कार्यक्रम के विवरण अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए	३४
अनुबंध VII: सुखम प्रशासन वेबिनार श्रृंखला के विवरण	३४

कार्यकारी सारांश

यह राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) की वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि २०१४ में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आश्रय में स्थापित एक उच्चस्तरीय स्वायत्त संस्थान है। यह दस्तावेज़ केंद्र द्वारा की गई गतिविधियों, प्रकाशनों, कार्यक्रमों, सहयोगों आदि का संक्षेप प्रदान करता है जो १ अप्रैल, २०२२ से ३१ मार्च, २०२३ तक केंद्र द्वारा की जाती है।

एनसीजीजी सुशासन, नीति सुधार, क्षमता निर्माण और भारत और अन्य विकासशील देशों के नागरिक सेवकों और तकनीकविदों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करता है। केंद्र एक सोच संगठन के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र श्रेष्ठ सुशासन, पारदर्शिता और सुधारी जनसेवा प्रदान करने वाले विभिन्न पहलों और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर जानकारी का राष्ट्रीय संग्रह स्थान के रूप में कार्य करता है। केंद्र ने विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य विकासशील देशों के नागरिक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है।

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के दौरान, एनसीजीजी ने मालदीव, गाम्बिया, बांगलादेश, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नागरिक सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति, जनसेवा प्रदान और सुशासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की। ये कार्यक्रम एनसीजीजी और संबंधित देशों / राज्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा थे। इसके अलावा, एनसीजीजी ने बांगलादेश और मालदीव के साथ समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार १,८०० और १,००० नागरिक सेवकों का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। ये प्रशिक्षण देशों के नागरिक सेवकों के बीच प्रशासन के अनुभवों को साझा करने का एक अवसर प्रदान करते हैं और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना में मदद करते हैं। वर्तमान वर्ष में एनसीजीजी ने मालदीव के नागरिक सेवकों के लिए १२ कार्यक्रम, बांगलादेश के नागरिक सेवकों के लिए ६ कार्यक्रम और गाम्बिया के नागरिक सेवकों के लिए १ कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर, एनसीजीजी ने जम्मू और कश्मीर के २,००० नागरिक सेवकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर प्रशिक्षित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर और सीमांत राज्यों में सरकारी सेवा प्रदान करने और सुशासन और जनसेवा प्रदान में सुधार करने के लिए, माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह, कर्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के नागरिक सेवकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में, १८ अगस्त, २०२२ को एनसीजीजी और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जहां अरुणाचल प्रदेश सरकार के कुल ५०० वरिष्ठ नागरिक सेवकों को पांच वर्षों में प्रशिक्षित किया जाने की योजना बनाई गई है। वर्तमान वर्ष में दो-दो कार्यक्रम दोनों राज्यों के लिए आयोजित किए गए।

केंद्र भी 'सार्वजनिक नीति और सुशासन: सिद्धांत और अभ्यास न्यू इंडिया में' एक पुस्तक लाने जा रहा है जिसमें प्रमुख नागरिक सेवकों, शिक्षाविदों और अभ्यासकर्ताओं द्वारा विभिन्न नीति निर्माण क्षेत्रों पर लेख शामिल हैं। एनसीजीजी ने स्मार्ट और स्थायी शहरों और डिजिटल सुशासन पर भी लेख प्रस्तुत किए हैं। ये प्रकाशन नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को देश के नागरिकों के लिए बेहतर नीतियों का अध्ययन करने और डिजाइन करने में मदद करने के लिए तैयार किए गए हैं। एनसीजीजी सतत प्रयास कर रहा है कि सरकारी शासन को सुधारने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में योगदान दें।

परिचय

I. केंद्र के बारे में

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) को सरकार द्वारा २०१४ में स्थापित किया गया था, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन एक उच्चस्तरीय स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया। केंद्र की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) से हुई, जो १९९५ में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनए) द्वारा स्थापित किया गया था। प्रारंभ में, इसका संचालन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा किया गया। हालांकि, ८ नवंबर २०१७ से, एनसीजीजी का प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग हुआ।

एनसीजीजी स्थानीय, राज्य, और राष्ट्रीय स्तरों पर सभी क्षेत्रों में सुखम प्रशासन और नीति सुधार, क्षमता निर्माण और भारत और अन्य विकसित देशों के सिविल सेवकों और भारत के प्रौद्योगिकीज्ञ का प्रशिक्षण करने के क्षेत्रों में काम करने के अधिकृत है। यह एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है।

II. एनसीजीजी के उद्देश्य और लक्ष्य

एनसीजीजी की स्थापना के समय निम्नलिखित उद्देश्यों को पहचाना गया है:

- i.) प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के मध्य एवं शासन एवं नीतिगत सुधारों के लिए विचार-मंडल होना,
- ii.) श्रेष्ठ कार्य-प्रणालियां, पहल और पद्धतियां जो सुशासन, ई-गवर्नेंस, नवाचार, और सरकार के भीतर परिवर्तन-प्रबंधन को प्रोत्साहित करें, के राष्ट्रीय सूचना कोष के रूप में कार्य करना।
- iii.) राष्ट्रीय/ राज्य और स्थानीय स्तर पर विनियामक और विकासात्मक प्रशासन, लोक नीति, शासन और लोक प्रबंधन के विविध पहलुओं पर सक्रिय शोध तथा क्षमता निर्माण कार्य शुरू करना और उनमें सहभागिता करना।
- iv.) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्य सरकारों के बीच सहक्रियाशीलता विकसित करना और शासन में प्रमुख मुद्दों पर परामर्श देना।



- v.) शासन में नवाचारी विचारों और श्रेष्ठ प्रथाओं की साझेदारी और रेप्लिकेशन तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन देना।
- vi.) देश के भीतर और बाहर परामर्श सेवा कार्य करना।
- vii.) सरकार के भीतर और बाहर शोधरत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ पारस्परिक संवाद।

III. एनसीजीजी का प्राधिकृत्य

- i.) नीति सुधार और साक्षर आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना;
- ii.) सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की डिज़ाइन और प्रारंभ करना;
- iii.) गवर्नेंस मुद्दों के प्रैक्टिकल समाधान उत्पन्न करने के लिए व्यापक शोध और विश्लेषण कार्यक्रम चलाना;
- iv.) विकसित देशों के कई साथी विचार विमर्श करने के लिए जानकारी, ज्ञान, विचार, और शासन में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने के लिए सहयोग करना;

- v.) विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रिपोर्ट, केस स्टडी, मॉनोग्राफ्स, और सर्वश्रेष्ठ अभियान्त्रिकों को प्रकाशित करें; और
- vi.) नागरिक केंद्रित शासन के लिए आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों और संपर्क का उपयोग करें।

IV. शासी निकाय

एनसीजीजी के कार्यों का प्रबंधन संचालन परिषद के समग्र मार्गदर्शन और मार्गनिर्देश के तहत किया जाता है, जिसका मुख्य अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। इसमें भारत सरकार के ९ मंत्रालयों/विभागों के सचिव होते हैं और इसमें ५ व्यक्तियों के लिए प्रावधान होता है, जैसे शिक्षाविद, प्रमुख प्रशासक, विशेषज्ञ, प्रमुख नवाचारक, प्रमुख संस्थानों के मुख्य। एनसीजीजी के मुख्य कार्यकारी, जो प्रबंधन परिषद का सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं, उन्होंने प्रबंधन परिषद के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य किया। प्रबंधन परिषद का संरचना अनुबंध –I में दी गई है।

V. प्रबंधन समिति

एनसीजीजी के पास एक प्रबंधन समिति है, जो वार्षिक योजनाओं, मॉनिटरिंग, और कार्यक्रमों के प्रबंधन के



संदर्भ में समाज के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, समाज के योजनाओं, योगदानों, और निधियों के संचालन के साथ। प्रबंधन समिति का प्रमुख अध्यक्ष के रूप में डीएआरपीजी के सचिव द्वारा किया जाता है, और इसमें भारत सरकार के ९ मंत्रालयों/विभागों के सचिव या उनके प्रतिनिधि, कैबिनेट सचिवालय से सचिव समन्वय, एसएस एंड एफए (एमएचए) के रूप में सदस्य, और एनसीजीजी के निदेशक महासचिव के रूप में कार्य करते हैं। संरचना अनुबंध -II में दी गई है।

२०२२-२३ में एनसीजीजी की गतिविधियाँ

I. मालदीव के नागरिक सेवकों का क्षमता निर्माण

वर्षों के साथ, एनसीजीजी ने खुद को क्षमता निर्माण और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में एक विशेष स्थान बनाया है। प्राविधिक मामलों के लिए नागरिक सेवकों और प्रौद्योगिकों के लिए अत्यधिक अनुकूलित क्षमता विकास कार्यक्रम विकसित करने और आयोजित करने के लिए, विदेश मंत्रालय (मीए) ने एनसीजीजी को मुख्य संस्था के रूप में पहचाना है। उसी तरह, डीएआरपीजी द्वारा घरेले नागरिक सेवकों और प्रौद्योगिकों के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए एनसीजीजी से

पूछा जाता है। सीबीपी जो एनसीजीजी द्वारा आयोजित किए गए हैं, उन्हें निम्नलिखित दो श्रेणियों में किया जाता है:

A. अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम: इस वर्ष, एनसीजीजी ने ३ देशों के ६१८ नागरिक सेवकों के लिए १९ बैचों में अनुकूलित क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित और आयोजित किए।

i.) **मालदीव:** माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ८ जून, २०१९ को आयोजित राज्य दौरे के दौरान, भारत और मालदीव ने एक समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत अगले ५ वर्षों में मालदीव के १,००० सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने की योजना बनाई। तब से २२ क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें भारत में मालदीव गणराज्य के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि समूह के लिए एक सप्ताह की अध्ययन यात्रा भी शामिल है।

२०२२-२३ के दौरान, मालदीव गणराज्य के ३६० नागरिक सेवकों ने १२ बैचों में प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे मार्च २०२३ तक प्रशिक्षित नागरिक सेवकों की कुल संख्या ६३५ तक पहुंच गई। क्षमता निर्माण कार्यक्रम की विवरण अनुबंध -III में है।



ii.) **बांग्लादेश:** २०१३ में, विदेश मंत्रालय ने एनसीजीजी को बांग्लादेश के १,५०० नागरिक सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यापित किया। १,५०० नागरिक सेवकों के सफल प्रशिक्षण के बाद, बांग्लादेश सरकार के लोक प्रशासन मंत्रालय ने ११ फरवरी २०१९ को एनसीजीजी के साथ एक समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत आगामी छह वर्षों में बांग्लादेश के अगले १,८०० नागरिक सेवकों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाने वाला है। इस समझौते के तहत, एनसीजीजी ने अब तक ११ बैचों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। २०२२-२३ के दौरान, छह बैचों में से २३४ बांग्लादेश गणराज्य के नागरिक सेवकों को प्रशिक्षण मिला, जिससे मार्च २०२३ तक प्रशिक्षित नागरिक सेवकों की कुल संख्या ३८२ तक पहुंच गई। विवरण अनुबंध -IV में दिए गए हैं।

iii.) **गाम्बिया:** एनसीजीजी ने डीएआरपीजी और विदेश मंत्रालय (मीए) के सहयोग से, १६ - २१ मई, २०२२ को गाम्बिया के २४ वरिष्ठ नागरिक सेवकों के लिए एक सप्ताह की क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे कुल संख्या ४९ हो गई।

इस कार्यक्रम का खास डिज़ाइन गाम्बिया के सिविल सेवा में निर्णयकर्ताओं को लैस करने के लिए था, जैसे स्थायी सचिव, उनके सहायक, और अन्य अधिकारी, जो एक बढ़ते हुए और परस्पर आश्रयी दुनिया में प्रभावी जन नीति बनाने के लिए नवीनतम ज्ञान, कौशल, और उपकरणों से लैस होने के लिए था। प्रशिक्षण का उद्देश्य श्रेष्ठ शासन और विकास को बढ़ावा देना था, साथ ही दुहराते प्रयासों से बचने के लिए देश-देश की व्यापक प्रदर्शनी देना था।

B. राष्ट्रीय कार्यक्रम: २०२२-२३ के दौरान, एनसीजीजी द्वारा जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से ४ बैचों में ११८ अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विवरण निम्नलिखित हैं:

i.) **जम्मू और कश्मीर:** १ जुलाई-२ जुलाई, २०२१ को श्रीनगर में आयोजित "श्रेष्ठ शासन प्रथाओं की पुनराचरण की क्षेत्रीय सम्मेलन" के दौरान, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर); पीएमओ; कार्मिक, जन शिकायतें और पेंशन; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह के घोषणाओं के



अनुसरण में, जम्मू और कश्मीर प्रबंधन, लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (जे एवं के इम्पाआरडी) और एनसीजीजी के बीच २,००० जम्मू और कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों को जन नीति और श्रेष्ठ शासन पर प्रशिक्षित करने के लिए एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया है। २०२२-२३ के दौरान, २ बैचों में से ६७ जम्मू और कश्मीर के नागरिक सेवकों को एनसीजीजी पर प्रशिक्षण मिला, जिससे मार्च २०२३ तक प्रशिक्षित नागरिक सेवकों की कुल संख्या १५८ तक पहुंच गई। विवरण अनुबंध -V में हैं।

ii.) **अरुणाचल प्रदेश:** १८ अगस्त, २०२२ को, डीएआरपीजी, भारत सरकार; अरुणाचल प्रदेश सरकार, प्रशासनिक सुधार विभाग; और एनसीजीजी के बीच अरुणाचल प्रदेश सरकार के ५०० वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक एमओयू हस्ताक्षर किया गया। २०२२-२३ के दौरान, एनसीजीजी ने अरुणाचल प्रदेश के ५१ अधिकारियों के लिए २ बैचों में अनुकूलित मॉड्यूल विकसित किया और प्रशिक्षण प्रदान किया। विवरण अनुबंध -VI में हैं।

C. परिचय यात्राएँ:

क्षमता निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा के रूप में, कक्षा में प्रशिक्षण को पूरक परिचय यात्राएँ की जाती हैं। ये यात्राएँ प्रतिभागियों को देश के इतिहास और संस्कृति, साथ ही नवीनतम प्रौद्योगिकी और आधारभूत विकास की समझ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। यहां कुछ ऐसी क्षेत्रीय यात्राएँ शामिल हैं:

- i.) जिला यात्राएँ: डीएम/एसडीएम प्रतिलिपि कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, प्राशासनिक और उप-डिवीजन स्तर के प्रशासन के कार्यवर्णन और कार्यकरण के बारे में सीखने के लिए प्राधिकृतियों को जिला और उप-डिवीजन के स्तर के प्रशासन के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देती है।
- ii.) प्रक्षिपण यात्राएँ पार्लियामेंट, दिल्ली मेट्रो, शून्य नेट ऊर्जा भवन - इंदिरा पर्यावरण भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों/कार्यालयों की प्रक्षिपण यात्राएँ।
- iii.) स्थानीय यात्राएँ: कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, अधिकारीगण को आगरा में ताज महल की यात्राओं पर लिया जाता है। उन्हें स्थानीय धरोहर और संस्कृति की मूल्यांकन करने के लिए स्थानीय दर्शन की भी यात्राएँ की जाती हैं।



II. राष्ट्रीय श्रेष्ठ शासन वेबिनार सीरीज़ (एनजीजीडब्ल्यूएस)

२०२२-२०२३ में, डीएआरपीजी और एनसीजीजी के सहयोग से, एक संग्रहित राष्ट्रीय श्रेष्ठ शासन वेबिनार सीरीज़ का आयोजन किया गया। इन वेबिनारों में श्रेष्ठ शासन पहल के अंतर्गत विभिन्न थीम्स पर ध्यान केंद्रित थे, जिन्हें प्रधानमंत्री की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार से मान्यता प्राप्त थी। इन वेबिनारों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, और सामाजिक क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को समाहित किया, जहाँ राज्यों को उनके असाधारण काम के लिए पुरस्कृत किया गया था। इन वेबिनारों का प्रमुख उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं और पुरस्कृत प्राप्तियों को अन्य राज्यों के लिए अनुकरण के रूप में प्रसारित करना था। प्रधानमंत्री पुरस्कृत पहल की वेबिनार सीरीज़ की विवरण अनुबंध - VII में दी गई है और निम्नलिखित है:

i.) २८ अप्रैल, २०२२ को, प्रथम वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा प्रदान को सुधारने पर ध्यान केंद्रित था। इसने कर्नाटक सरकार की सकला पहल का अवलोकन प्रदान किया। सकला एक ऐसा क़ानून है जिसके तहत सूचित की गई सेवाएँ प्रावधानित समय सीमा के अंदर प्रदान की जाएंगी, जिसके खिलाफ मांग पर उपभोक्ता को उपभोक्ता द्वारा दावा किये जाने पर प्रतिपूरक लागत देनी होगी

दी गई मुआवजा उसके विलंब के लिए जिम्मेदार पब्लिक सर्विस अधिकारी(ओं) से उधार लिया जाता है। कर्नाटक नागरिकों को समय-सीमित सेवा प्रदान में सफलता का उदाहरण है। कर्नाटक नागरिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रबंधित, यह कार्यक्रम मिशन मोड में चल रहा है और राज्य के सभी ३० जिलों में ५० से अधिक विभागों में सेवा प्रदान के लिए ई-सरकार मेकेनिज़म का प्रभावी रूप से उपयोग कर रहा है।

ii.) स्वास्थ्य श्रेणी के तहत दूसरा वेबिनार २७ मई, २०२२ को आयोजित किया गया था। इसका मुख्य ध्येय राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधी प्रणाली को सुधारने के लिए चित्तौड़गढ़ जिले के जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे पहलों पर समर्पित था, जिसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए दवाओं को सस्ते बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना था। इस पहल के अंतर्गत, डॉक्टरों से मांग की गई कि महंगी ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ते जेनेरिक दवाओं का प्रेस्क्राइब किया जाए, सरकारी नियंत्रण के तहत सहकारिता स्टोर्स के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएँ खरीदी जाएँ और मरीजों और उनके परिवारों के बीच जेनेरिक दवाओं के उपयोग और उनके संभावित लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए।



इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, जिलों में कम लागत की दवा दुकानें (फेयर प्राइस शॉप्स) स्थापित की गई हैं, जिससे दवाओं की कीमत कम हो गई है और व्यक्तियों के लिए पहुंचने वाली हो गई है, और उनके लिए सम्पूर्ण उपचार की गारंटी है।

- iii.) आशापूर्ण जिलों कार्यक्रम (एडीपी) पर ३वें वेबिनार का आयोजन २४ जून, २०२२ को किया गया। इस वेबिनार का प्रमुख अतिरिक्त सचिव श्री अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ द्वारा किया गया था, जिसमें 'एक जिला एक उत्पाद' पहल (सिद्धार्थ नगर मॉडल) के माध्यम से समग्र विकास के विषय पर केंद्रित था और पोषण अभियान (आसिफाबाद मॉडल) में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए। इस वेबिनार के दौरान, जिला जिलाधिकारी (डीएम) ने परियोजना की योजना, डिज़ाइन, कार्यान्वयन, और मॉनिटरिंग प्रक्रिया को प्रस्तुत किया, अपनी प्राप्ति को हाइलाइट किया। उन्होंने यह भी साझा किया कि इन कार्यक्रमों के तहत जनसेवा प्रदान को बढ़ाने के लिए अधिक जनसंख्या तक पहुंचने के लिए उनकी रणनीतियों को कैसे विस्तारित करने के लिए वह भी साझा किया।
- iv.) ४वें वेबिनार का आयोजन २९ जून २०२२ को सार्थक जनसंकल्पों के संबंध में किया गया था। सरकार का उद्देश्य एक बहु-चैनल एकल खिड़की डिलीवरी प्रणाली स्थापित करना रहा है, जिससे नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं का स्थानीय स्तर पर मॉडर्न आईटी प्रौद्योगिकी का सबसे कुशल तरीके से पहुंचने की अनुमति देता है। ४वें वेबिनार का मुख्य ध्यान प्रजावाणि-जनहित पहल और सरकार आपके द्वार पहल पर था।
- v.) जनसंपर्क और शिकायत प्रबंधन प्रणाली जिसे प्रजावाणि-जनहित के नाम से जाना जाता है, राजन्ना सिर्सिल्ला जिले में आयोजित किया गया था ताकि सूचित सेवाओं की समय पर वितरण की गारंटी हो। किसी भी देरी के मामले में,

आवेदक संवाद के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एक बार जब उनकी शिकायतें हल हो जाती हैं, तो वे इन स्रोतों के माध्यम से प्रक्रिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। 'सरकार आपके द्वार' पहल एक स्मार्ट, नागरिक केंद्रित पहल है जो सारे प्रकार की सरकार से नागरिक (जीरसी) और सरकार से व्यापार (जीरबी) सेवाओं के लिए एक एकल प्रवेश स्थान का सुन्दर उपयोग करता है, विशेष रूप से सबसे दूरस्थ स्थानों पर।

- vi.) पब्लिक सर्विस प्रदान के क्षेत्र में ६वें वेबिनार का आयोजन ३० सितंबर, २०२२ को किया गया। इस ६वें वेबिनार का प्रमुख अतिरिक्त सचिव श्री वी. श्रीनिवास, डीएआरपीजी और डीपीपीडब्ल्यू के सचिव, ने किया, जिसमें सिंगापुर सरकार के सार्वजनिक सेवा विभाग के स्थायी सचिव श्री लो खुम यीन ने मुख्य भाषण के रूप में भाग लिया। वेबिनार के फोकस में 'एनडीएमसी एपीपी ३११' और 'सेवा सिंधु पोर्टल' दो पहलों पर था। 'एनडीएमसी एपीपी ३११' दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा एक नागरिक संबंध और शिकायत प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए एक पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित सेवाओं की समय पर वितरण की गारंटी देना है। किसी भी देरी के मामले में, आवेदकों को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपनी शिकायतें साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब समस्या सुलझा ली जाती है, तो व्यक्तियों को विभिन्न प्रतिक्रिया माध्यमों के माध्यम से समाधान प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सेवा सिंधु एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कर्नाटक में ७४ विभागों, बोर्डों और कॉर्पोरेशन्स द्वारा प्रदान की जाने वाली ८०० से अधिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म बहुत लाभदायक साबित होता है क्योंकि यह लोगों को समय और पैसे दोनों की बचत करने की सुविधा प्रदान करता है और सरकार से संबंधित प्रक्रियाओं को सुगठित करता है।



vii.) ७वें वेबिनार जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर २८ अक्टूबर, २०२२ को आयोजित किया गया था। इस वेबिनार का फोकस लोगों की भागीदारी पर था, स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (गुजरात मॉडल) और स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (मध्य प्रदेश मॉडल) में।

महेसाणा, जिसमें ६५८ गांव और ६०५ ग्राम पंचायतें हैं, ने कई चुनौतियों को पार किया और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या एसबीएम(जी) को सफलतापूर्वक लागू किया। टॉयलेट निर्मित करने में आ रहे अड़चनों के बावजूद, जैसे कि टॉयलेट निर्माण के लिए रास्ता नहीं बनाने की कठिनाइयों, अशिक्षता, सामाजिक नियमों और खुले में मल त्याग की प्रचलित आदत, साथ ही टॉयलेट के लिए सीमित पानी की आपूर्ति और गरीबी रेखा (बीपीएल) और वेतन वालों की मानसिकता के जैसे मुद्दों का सामना करते हुए, महेसाणा ने यह साबित किया कि वह साहसी रूप से आगे बढ़ता है। इंदौर ने 'कचरा प्रबंधन और सफाई' मॉडल को लागू किया है, जिसमें सक्रिय जनसंघटन पर निर्भर है। लोगों, जनसंघटन प्रतिष्ठाताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोगी उपलब्धियों के प्रमाण

के रूप में, इंदौर को २०१७ से २०२२ तक लगातार 'भारत का सबसे स्वच्छ शहर' का उपनाम मिला है।

viii.) केंद्र और राज्य में नवाचार पर ८वें वेबिनार का आयोजन २५ नवंबर, २०२३ को किया गया। नवाचारी पहल में भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) और 'एक देश, एक राशन कार्ड' जो खाद्य और जनसंप्रेरण विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है। एनजीडीआरएस एक विविध और अनुकूलनीय एप्लीकेशन है जो राष्ट्रव्यापी पंजीकरण विभागों के लिए विकसित किया गया है। इसका सब-रजिस्ट्रार, नागरिकों और इन विभागों के अपेक्षा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एनजीडीआरएस राज्यों को अपनी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर को अनुकूलनीय स्थान बनाने और विन्यासित करने की अनुमति देता है। संपत्ति और दस्तावेज पंजीकरण के लिए एक उपयोगकर्ता-मित्रपूर्ण इंटरफ़ेस के साथ, यह एप्लीकेशन नागरिकों को ऑनलाइन भूमि खरीदी में सुविधा पूर्वक शामिल होने की अनुमति देता है। वे चक्र दरों के बारे में जानकारी

प्राप्त कर सकते हैं, प्राचलित दरों के आधार पर संपत्ति मूल्य की गणना कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की ज़मीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना योग्य लाभार्थियों को अपने गृह राज्य के राशन कार्ड का उपयोग देश के किसी भी हिस्से में लाभ उठाने के लिए संभव बनाती है। यह व्यक्तियों और प्रवासी मजदूरों को अलग-अलग राज्यों में यात्रा या प्रवास करते समय अलग राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा और कल्याण उपायों की बाधाओं के बिना उपचार उपलब्ध होता है।

- ix.) ९वें वेबिनार पर हर घर जल योजना के बारे में ३० दिसंबर, २०२२ को आयोजित किया गया था। इस वेबिनार में जलगांव (महाराष्ट्र) के नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट और ग्रामीण क्षेत्रों में नृत्यत्मक पीने के पानी की वितरण दृष्टिकोण (गुजरात मॉडल) के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट का प्रमुख ध्यान जल का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने और पीने और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह विभिन्न जल चैनलों को जोड़कर होता है, और इसका उद्देश्य सफल नदी जोड़ने प्रोजेक्ट के डिज़ाइन और उपलब्धियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करना भी है। इस पहल ने प्रदेश के पूरे क्षेत्र में सिंचाई और मानव उपभोग के लिए पर्याप्त पानी प्रदान किया है। ‘ग्रामीण क्षेत्रों में नृत्यत्मक पीने के पानी की वितरण दृष्टिकोण’ गुजरात सरकार द्वारा किया गया एक उदाहरणीय अच्छी शासन पहल है। इसका उद्देश्य सभी निवासियों को पहुंचने और पोर्टेबल पीने के पानी प्रदान करना है, जिसमें गुजरात में सतह और भूमि संदर्भ में प्राकृतिक विविधता को मध्यस्थ किया गया है, जो सतह और भूमिजल संसाधनों पर प्रभाव डालती है। इस पहल में सरकार की विश्वासिलता को दिखाया गया है कि

वास्मो, पानी समिति और महिलाओं की शामिली द्वारा ग्रामीण समुदायों के लिए सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करने की दिशा में।

- x.) १०वें वेबिनार पर जिला स्तर पर नवाचारों पर ध्यान केंद्रित था जिसे २३ जनवरी, २०२३ को आयोजित किया गया था। इस वेबिनार में मणिपुर सरकार द्वारा शुरू की गई पहल “ब्लीड विथ प्राइड” (इम्फाल पूर्व) और मध्य प्रदेश सरकार के खंडवा जिले की “लोक सेवक” पहल की प्रमुखता थी।

मणिपुर सरकार अपने इस पहल के माध्यम से गाँवी क्षेत्रों की किशोरी किशोरियों को मासिक धर्म समझाने में सशक्ति प्रदान कर रही है और बड़े पैमाने पर समुदाय को मासिक धर्म समझाने में मदद की है। इसके परिणामस्वरूप यह माध्यमिक शिक्षा में अनुपस्थिति को कम किया है, जिससे पूर्णात्मक विकास और विकास हुआ है। खंडवा जिले के जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई लोकसेवक ऐप एक अद्वितीय और नवाचारी दृष्टिकोण को प्रमोट करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसने न केवल यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और कार्यालय जाते हैं, बल्कि यह सार्वजनिक के लिए विभिन्न सरकारी पहलों के लिए बेहतर पहुँच और समय पर समाधान की सुनिश्चिति भी दी है।

- xi.) ११वें वेबिनार पर लक्ष्य-साधन क्षेत्र (एडीपी) के बारे में आयोजित किया गया था, जिसमें गोलपाड़ा (असम) और कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर) के दो जिलों पर ध्यान केंद्रित था। जिला स्तर पर सरकार की कुछ महत्वपूर्ण पहलों में से एक एडीपी नियमित अंतरालों में वास्तविक समय डेटा संग्रह के माध्यम से विकास की प्रगति का मापदंड बनता है। इसकी मूल दर्शनिका प्रगति का मापना और प्रबंधन करना है, जिसमें भूमिका निर्धारित करने के लिए सेट पैरामीटर होते हैं।

यह कार्यक्रम केंद्र से पंचायत स्तर तक विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और हर भागीदार के लिए स्पष्ट भूमिका निर्धारित करता है, जिससे कार्यक्रम के लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासों को निर्देशित किया जाता है। नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग के प्रस्तावना से इस कार्यक्रम की विशिष्टता बढ़ती है, क्योंकि इसमें अधिकतम संभव वृद्धि पर ध्यान केंद्रित होता है न कि अधिकतम विकास, जिससे अपेक्षाकृत विपरीत जिलों के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। अंततः, यह कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद के एक अद्वितीय मॉडल का उदाहरण है। सितंबर २०२२ में, एडीपी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में शुरू किया गया था। इससे पहले जहाँ आतंकवादी तत्वों की भारी मौजूदगी थी, कुपवाड़ा अब उत्तर भारत के अग्रणी जिलों में से एक के रूप में सामने आया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने राष्ट्रीय आकांक्षी जिले कार्यक्रम की पहली स्वतंत्र मूल्यांकन में स्वीकार किया है।

- xii.) नमामि गंगे पर ३१ मार्च, २०२३ को १२वीं वेबिनार आयोजित किया गया। इसका मुख्य ध्यान उत्तराखंड के चमोली और उत्तरकाशी जिलों पर था। गंगा नदी को साफ करना एक लगातार प्रयास है, इसे मान्यता देते हुए भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों का समर्थन करती है जिसमें वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस कार्यक्रम में कई प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं, जिनमें स्वच्छ जल उपचार, कचरा प्रबंधन, नदी के किनारे का प्रबंधन, निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना, ग्रामीण स्वच्छता, वनों का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जनसहभागिता शामिल हैं। यह योजना गंगा नदी के बेसिन प्रबंधन योजना (जीआरबीएमपी) का पालन करती है, जिसे आईआईटी-कानपुर के नेतृत्व में संघ के ७ आईआईटी के संघ ने

तैयार किया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) के प्राथमिक उद्देश्य प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और गंगा नदी को पुनर्जीवित करना है, जिसे नदी बेसिन दृष्टिकोण के माध्यम से अपनाकर व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए इंटर-सेक्टरीय समन्वय को बढ़ावा देना और पानी की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संचालनशीलता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम पारिस्थितिकी धाराओं को बनाए रखना है।

III. प्रकाशन

a.) लेख

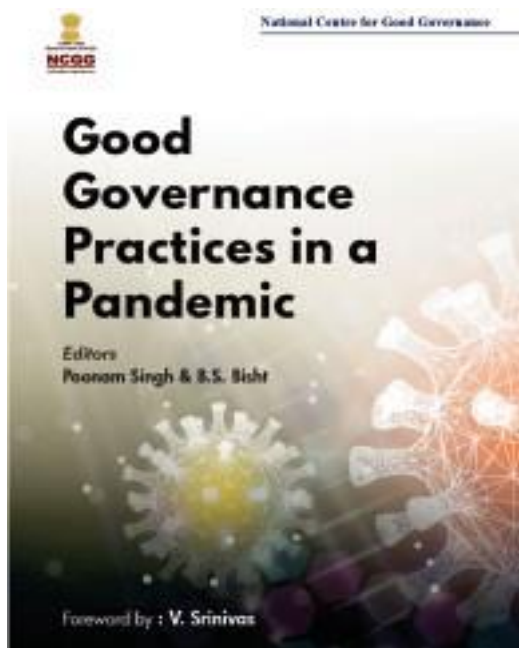
एनसीजीजी ने लेख प्रकाशित किए हैं, जो शासन, पानी, युवा, नेतृत्व, और नवाचार से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करते हैं।

- i.) डीजी, श्री भारत लाल द्वारा लिखे गए लेख 'हमारी युवा शक्ति की उत्कृष्टता को पोषण' का फरवरी महीने के विकासी मासिक - 'योजना मैगजीन' में प्रकाशित किया गया था। भारत के युवा देश के प्रतिष्ठान और संभावना के सबसे बड़े दूत रहे हैं। लेख विस्तार से बताता है कि अवसर और उनकी आकांक्षाओं ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है।
- ii.) भारत जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि उच्च आर्थिक विकास को बनाए रख सके और स्टैकहोल्डर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहा है, जो देश में जल प्रबंधन के लिए अपने अनुभव, ज्ञान, नवाचार, और तंत्रों को साझा कर सकते हैं। जी-२० सचिवालय के फरवरी मासिक पत्रिका के संकेताचारक ने आर्थिक विकास की कुंजी के रूप में जल सुरक्षा पर एक लेख लिखा है।



b.) पुस्तकें

- i.) एनसीजीजी ने 'सार्वजनिक नीति और शासन: नये भारत में सिद्धांत और अभ्यास' नामक एक पुस्तक तैयार की है जिसमें अनुभवी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए २६ लेख शामिल हैं। यह विभिन्न विषयों के विशेषज्ञता के क्षेत्र से ज्ञान, ज्ञान और अनुभवों को समावेश करती है और इसे प्रकाशित किया जाना है।



- ii.) केंद्र ने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है, जिसका नाम 'महामारी में श्रेष्ठ शासन के अभ्यास' है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर के अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य संकट को संघर्ष करने के लिए अपनाए गए अभ्यासों का मूल्यांकन, समीक्षा और सूचीकरण करना है।

c.) पत्र

डॉ. बी. एस. बिष्ट, सहायक प्रोफेसर, एनसीजीजी ने 'स्मार्ट और स्थायी शहर निर्माण: एक मामला अध्ययन - उत्तराखंड, भारत के देहरादून शहर की' नामक एक पत्र का लेखन किया। इस पत्र में पाया गया कि बुद्धिमान यातायात संकेत नियंत्रक ने यातायात प्रवाह और सड़क सुरक्षा को सुधारा, जबकि स्वचालित यातायात प्रणाली ने व्यस्त सड़कों की पहचान की और वाहन वर्गीकरण रिपोर्ट उत्पन्न की। देहरादून शहर की निगरानी प्रणाली ने पुलिस को शहर की केंद्रीय कमांड और नियंत्रण केंद्र से नजरबंद रखकर अपराध दूरों को कम किया। स्वचालित चेतावनियां जारी की गईं और तत्परता से पुलिस कर्मचारियों द्वारा समस्याओं का समाधान किया गया, जिससे नागरिकों और शहरी परिवहन योजनाओं को लाभ मिला। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप अन्य सरकारी सार्वजनिक सेवा नवाचारों तक फैलते हैं। आईआईएम

ये मामला अध्ययन अन्य सरकारी सार्वजनिक सेवा नवाचारों में डिजिटल रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए मूल्यवान अवधारणाओं को प्रदान करते हैं।

IV. सहयोग

एनसीजीजी, शासन, सुधार, क्षमता निर्माण, परिवर्तन प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में जानकारी, ज्ञान, विचार और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए सहयोग पर महत्व देता है। सार्वजनिक नीति और शासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए, एनसीजीजी ने विभिन्न देशों और संस्थाओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- i.) ८ जुलाई, २०२१ को, भारत सरकार के डीएआरपीजी और गाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति के कार्यालय के सार्वजनिक सेवा आयोग ने ३ वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारी प्रशासन और शासन सुधारों को संवर्धित करने में सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

- ii.) ३१ जनवरी, २०२२ को, सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार के लिए केंद्र (सीआईपीएस) और एनसीजीजी ने ३ वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य एनसीजीजी और सीआईपीएस के बीच बुद्धिजीवी अंतरक्रिया को बढ़ावा देना है, जैसे ज्ञान का आपसी आदान-प्रदान करना और पुनर्निर्माण के लिए संभावना रखने वाले नवाचारिक मॉडलों का साझा करना, दलगत और आगंतुक दलों को मेजबानी और यात्रा कराना, संयुक्त कार्य में सहयोग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का साझा करना और प्रासंगिक प्रकाशनों का आपसी आदान-प्रदान करना।

- iii.) ११ मार्च, २०२२ को, आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस और एनसीजीजी ने ५ वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य इससे संबंधित क्षेत्रों में शामिल हैं जैसे प्रशासनिक प्रथाओं में श्रेष्ठताओं के आधार पर मामलों की अध्ययन रिपोर्टें बनाना और उन्हें व्यापक अपनाने और पुनर्निर्माण के लिए प्रसारित करना, साथ ही प्रशासनिक सुधारों पर अनुसंधान अध्ययनों को आयोजित करना जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शासन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।



- iv.) २९ जुलाई, २०२१ को, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) विशाखापत्तनम और एनसीजीजी ने ५ वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य संयुक्त रूप से शैक्षणिक शीर्षक प्रदान कार्यक्रमों की खोज करना, संसाधन साझा करने में सहयोग करना, संस्थानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार संयुक्त परामर्श और अनुसंधान परियोजनाओं में विशेषज्ञ शिक्षकों को शामिल करना, साथ ही साझी रुचि के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देना, संयुक्त गतिविधियों पर सहयोग करना और शैक्षणिक शिक्षकों और शोधकर्ताओं का आपसी विनिमय सुविधा को सुविधाजनक बनाना है।
- v.) ९ अगस्त, २०२१ को, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) इंदौर और एनसीजीजी ने ३ वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य शैक्षणिक कर्मचारियों और छात्रों के बीच आपसी विनिमय और सहयोग को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना है, डिग्री प्रदान कार्यक्रमों की खोज करना, संसाधनों का सहयोग और साझा करना, दोनों संस्थानों के दिशा-निर्देशों के अनुसार संयुक्त परामर्श और अनुसंधान परियोजनाओं में शिक्षक विशेषज्ञों को शामिल करना, सार्वजनिक प्रशासन और श्रेष्ठ शासन पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना और आयोजन करना, संयुक्त रुचि के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना, संयुक्त सामाजिक पहलों में सहयोग को सुविधाजनक बनाना, नीति तैयारी, श्रेष्ठ शासन सूचकांक रैंकिंग, और शिक्षा और प्रशिक्षण के उद्देश्यों के लिए शोध और शैक्षणिक डेटा का आपसी विनिमय करना है।
- vi.) १३ जुलाई, २०२१ को, जम्मू और कश्मीर सरकार के तहत जेएंडके प्रबंध संस्थान, सार्वजनिक प्रशासन और ग्रामीण विकास (जेएंडके-आईएमपीआरडी), और एनसीजीजी ने ५ वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच शैक्षणिक और बौद्धिक अंतरभाषा की स्थापना, संचालन और सुधार करना है। समझौते में २०१७ के सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी), और ई-खरीदारी के संबंध में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अभ्यासों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए २००० वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण गतिविधियाँ भी शामिल हैं, खासकर जीईएम पर ध्यान केंद्रित करके। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आईएसएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ मध्यकार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए है।
- vii.) १७ जनवरी, २०२२ को, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) हैदराबाद और एनसीजीजी ने ३ वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सेवा प्रदान क्षेत्र और श्रेष्ठ शासन के क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए अनुभव साझा करना और समरसता प्राप्त करना है। सहयोग में क्षमता निर्माण कार्यक्रम, संयुक्त परियोजनाएं, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, संसाधन व्यक्तियों का आपसी विनिमय, मेजबानी और दौरयान दलों का स्वागत, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का साझा करना, और संबंधित प्रकाशनों का आपसी विनिमय शामिल है।

V. संवाद क्रियाएँ

श्री भारत लाल, महानिदेशक, ने विभिन्न संस्थानों और संगठनों द्वारा आयोजित कई घटनाओं, सम्मेलनों, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

a) घरेलू:

महानिदेशक ने एक सत्र का माध्यस्थ किया जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में आयोजित दो-दिन के क्षेत्रीय सम्मेलन में हुआ। इस श्रेष्ठ प्रशासन सम्मेलन का मुख्य ध्यान ई-सेवा प्रदान पर था। उन्होंने विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'विमर्ष' में भारत में जल सुरक्षा पर भाषण भी दिया। महानिदेशक ने १४वीं दक्षिण एशिया कांफ्रेंस पर भी मुख्य भाषण दिया, जिसका

आयोजन मनोहर परिकर-आईडीएसए द्वारा किया गया था, 'थिंक २० एटी जी२०: एक प्रतिरोधी दक्षिण एशिया की ओर'। उन्होंने ओब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'साइफाई' जैसे संगठनों के संगठनों की समर्थन के साथ तकनीक, समाज, और सुरक्षा पर कुंभक संवाद में भी मुख्य भाषण दिया। एनसीजीजी के महानिदेशक ने ओब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय की मदद से आयोजित रायसीना डायलॉग में भी एक सत्र का माध्यस्थ किया।

वे अहमदाबाद प्रबंध संघ, अहमदाबाद; भारतीय प्रबंधन संघ, अहमदाबाद; भारतीय लोक प्रशासन संघ, नई दिल्ली; भारतीय वन प्रबंधन संघ, भोपाल; टेरी, नई दिल्ली, आदि जैसे विभिन्न संगठनों के लिए मुख्य भाषण भी दिए। विभिन्न संगठनों पर, उन्होंने जल सुरक्षा, बुद्धिमान जल प्रबंधन, और प्रत्येक घर में सुरक्षित और विश्वसनीय पाइपड जल आपूर्ति के लिए नवाचारी समाधानों पर बोला, जैसे-जैसे प्रशासनिक कार्यों के बारे में।

महानिदेशक ने विभिन्न विषयों पर भाषण भी दिए, जैसे कि श्रेष्ठ शासन के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का डिजिटलीकरण पर वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन में; जल जीवन मिशन - लाभ, चुनौतियाँ और आगे की योजना पर कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में; लोक नीति, शासन और नवाचार पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में; श्रेष्ठ शासन में AI की भूमिका पर 'डिजिटल रेडीनेस फॉर पब्लिक सेक्टर लीडर्स' कार्यक्रम के शुभारंभ पर कॉमनवेल्थ सचिवालय, लंदन और इंटेल् इंक, यूएसए के साथ; उसने नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी - डी'अमोर-मैकिम स्कूल ऑफ बिजनेस, यूएसए में कीनोट भाषण भी दिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के मंचों का भी मोड़रेट किया है, जैसे कि २०२३ में राइसिना संवाद में 'इंडिया लाइटहाउस - सभी को नलीय



b) अंतरराष्ट्रीय यात्राएँ:

एनसीजीजी की विभिन्न पहलों की समीक्षा करने और आगे बढ़ाने के लिए दो प्रतिष्ठानों ने मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की। उनके बारे में विवरण निम्नलिखित हैं: डीएआरपीजी

- i.) **मालदीव:** भारतीय प्रतिष्ठित नागरिक सेवा प्रशासन और विदेश मामले मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, एनसीजीजी के महानिदेशक श्री भारत लाल द्वारा नेतृत्व भारतीय प्रत्यावर्तन का दौरा मालदीव गणराज्य किया गया, जो १९ नवम्बर से २१ नवम्बर, २०२२ को हुआ। इस यात्रा का आयोजन भारतीय उच्च आयोग, मालदीव द्वारा किया गया था। इस दौरान, मालदीव की सिविल सर्विस कमीशन के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की गई, और भविष्य के कार्रवाई के बारे में भी चर्चा हुई। दल ने मालदीव सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से भी मुलाकात की, जैसे- विदेश संबंध, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, आदि, और भ्रष्टाचार और सेंट्रल सूचना कमीशन के मुख्यों से भी महत्वपूर्ण चर्चा की।

- ii.) **श्रीलंका:** श्री भारत लाल, एनसीजीजी के महानिदेशक द्वारा नेतृत्व, दल ने ३१ मार्च से १ अप्रैल, २०२३ के बीच श्रीलंका सरकार के आमंत्रण पर कोलंबो का दौरा किया। इस दौरान, उन्होंने श्रीलंका के सिविल सेवकों के साथ कई मीटिंग्स की, जिसमें नीति सुधार, श्रेष्ठ प्रशासन, डिजिटलीकरण, सामर्थ्य निर्माण, प्रशिक्षण, संस्थान निर्माण, और सार्वजनिक सेवा प्रदान की चर्चा की गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति, रणील विक्रमेसिंघे, ने भी इस दल से मुलाकात की और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने एनसीजीजी को श्रीलंका में शासन और सार्वजनिक नीति के विश्वविद्यालय की स्थापना और श्रीलंका के सिविल सेवकों की सामर्थ्य निर्माण में मदद करने की सीधी प्रार्थना की।

VI. संस्थागत विकास

- a.) **श्रेष्ठ प्रशासन के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना:** सिनर्जी विकसित करने और प्रयासों की जुटती हुई जोड़ने के लिए, प्रस्तावित है कि सार्वजनिक नीति, सुधार, श्रेष्ठ प्रशासन और सामर्थ्य निर्माण के क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न



संस्थानों को और डोमेन विशेषज्ञों को एक एकल राष्ट्रीय नेटवर्क में लाने का प्रस्ताव है, जहां ज्ञान, विचार, श्रेष्ठ प्रथाएँ, और मामले की अध्ययन और दर्शनीकरण के लिए संग्रहित, चर्चित, और दर्ज किए जाते हैं, जो व्यापक प्रसार के लिए हैं। एनसीजीजी विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों के समाधान खोजने में मदद करेगा और संबंधित नीति ढांचे को तालमेल के अनुसार समायोजित करने के लिए बदला जा सकता है। एक संस्थान या राज्य/संघ की विशेषज्ञता और शिक्षा को अन्यो के साथ साझा किया और उन्होंने अपनाया और बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, एनसीजीजी द्वारा निर्धारित के रूप में, श्रेष्ठ प्रशासन पर राष्ट्रीय ग्रिड को होस्ट करने की योजना है। यह ग्रिड नीति सुधार में एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेगा, प्रबंधन समस्याओं का समाधान करेगा, और सभी संबंधित प्रायोजकों के लिए उपयोगी ज्ञान, विचार, और श्रेष्ठ प्रथाओं की थोक संवाद की रखवाली करेगा। यह प्रस्तावित है कि ऐसा एक ग्रिड बनाया जाए और संबंधित प्रायोजकों के छोटे क्षेत्रीय और विषयगत कार्यशालाओं और उनके लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए।

b.) संसाधन व्यक्तियों को जोड़ना: केंद्र प्रशासनिक विभाग एक वेब-आधारित मंच विकसित करने पर काम कर रहा है जिसके माध्यम से प्रख्यात व्यक्तियों, क्षेत्रीय विशेषज्ञों, सिविल सेवकों, शिक्षाविदों और लोक प्रशासन और शासन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को एनसीजीजी की गतिविधियों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इन विशेषज्ञों को एनसीजीजी टीम के साथ मिलकर महत्वपूर्ण नीति और शासन संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण मॉड्यूल डिज़ाइन और विकसित करने में मदद करेंगे, साथ ही क्षमता निर्माण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, मॉड्यूल विकास अभ्यासों, मॉड्यूल विकास आदि में सहयोग करेंगे। ये संसाधन व्यक्तियों को केस स्टडीज, पीयर समीक्षा, अनुसंधान प्रस्तावों की जांच, विचारधारा आदि में संलग्न किया जाएगा। इस अवसर के साथ, केंद्र ई-प्रशासन, डिजिटलीकरण, नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा प्रदान और नीति सुधारों से संबंधित विषयों पर काम कर सकेगा।



c.) अनुसंधान योजना - राष्ट्रीय सार्वजनिक नीति और शासन प्रयोगशाला स्थापना: केंद्र प्रशासनिक विभाग नीति, शासन और सार्वजनिक सेवा प्रदान के क्षेत्र में सिद्धांत को आंतरित करने के लिए काम कर रहा है। एनसीजीजी ने अनुसंधान योजना विकसित की है, जिसके माध्यम से प्रख्यात विद्वान, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, सामाजिक वैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रीय विशेषज्ञ महत्वपूर्ण नीति मुद्दों और शासन पर अनुसंधान कर सकते हैं। इसके लिए, वरिष्ठ यात्री फेलोज (एसवीएफ) को दो वर्षों के लिए जोड़ा जाएगा, जो एक वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। इसी तरह के लोगों को एक ही स्थान पर मिलकर सामाजिक विज्ञान और शासन संबंधी मुद्दों में विचारों के उत्पन्न होने और प्रगति के लिए लाभदायक होगा, साथ ही उन्हें अपने खुद के गुणवत्ता अनुसंधान को पुरस्कृत करने का एक मंच भी मिलेगा। एनसीजीजी अपने उद्देश्यों के साथ एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विषय-संबंधी उपयुक्त अनुसंधान सामग्री और अध.

d) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व विकास कार्यक्रम (लीड्स): विभिन्न विज्ञान प्रशासकों के साथ हुई चर्चों के दौरान स्पष्ट हो गया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

नेतृत्व विकास की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक विभिन्न प्रयोगशाला, संस्थानों को अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने के लिए समर्थ हो सकें।

एनसीजीजी कई क्षेत्रों में है जहाँ उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, एनसीजीजी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (इन्सा) के साथ सहयोग कर वैज्ञानिक संस्थानों / प्रयोगशालाओं में नेतृत्व और अच्छी शासन प्रदान करने के लिए वैज्ञानिकों की क्षमताओं को विकसित करने का काम कर रहा है। यह विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों जैसे डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीआई, डीआरडीओ, आईसीएआर और अन्य प्रयोगशालाओं / संस्थाओं से विश्वसनीय अनुसंधान योग्यता वाले वैज्ञानिकों को संग्रहीत करता है। वैज्ञानिक इस अवसर के साथ विभिन्न विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसे संस्थान निर्माण, वैधानिक कार्य, शासन, अनुसंधान अनुसंधान, प्रबंधन, लैंगिक / विविधता मुद्दों, वैज्ञानिक मानदंड, वैज्ञानिक मानव संसाधनों की भर्ती और मेंटरिंग, उद्योग-प्रयोगशाला सहयोग, वित्तीय प्रबंधन, व्यक्तिगत संबंध, राष्ट्रीय आवश्यकताओं, संसाधन उत्पादन, प्रशासन, डिजिटल शासन आदि। इस कार्यक्रम के माध्यम



से, वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रशासन में उन्हें सामना करने की उम्मीद की जा सकती है।

e) इंटरनशिप कार्यक्रम: एनसीजीजी एक इंटरनशिप कार्यक्रम शुरू करने की प्रस्तावना रखता है, जिसका उद्देश्य भारत या विदेश में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों में पढ़ाई कर रहे स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों या शोध विद्यार्थियों को इंटरन के रूप में ले जाना है। एनसीजीजी इंटरनशिप कार्यक्रम का उद्देश्य युवा और उत्कृष्ट मस्तिष्कों को अनुसंधान, प्रलेखन और मामलों के अध्ययन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय संग्रहालय का विकास करने का है, शैक्षिक, अनुसंधान और शैक्षिक मंच स्थापित करने का। इंटरनशिप के क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और शासन, नवाचार और उद्यमिता, शिक्षा, विकेंद्रीकृत योजना, ई-शासन, सार्वजनिक सेवा प्रदान, कानून और नियम, ग्रामीण विकास और गरीबी निवारण, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य संचालन में शासन, स्थायित्व, आपदा प्रतिरोध संरचना और आपदा न्यूनीकरण, स्थायी शहरी प्रबंधन और शहरी शासन, बुनियादी ढांचा विकास, नवाचार और उद्यमिता, जल संसाधन प्रबंधन और नदी पुनर्जीवन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा, आदिवासी मामला, मॉनिटरिंग, डेटा विश्लेषण और मूल्यांकन, परियोजना योजना, डिजाइन, प्रबंधन और मॉनिटरिंग, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और वन, सामाजिक संचार और सामाजिक मीडिया आदि शामिल हैं। यह युवा छात्रों को सीखने और योगदान देने का भी अवसर प्रदान करेगा। इंटरनशिप की अवधि कम से कम ८ सप्ताह और अधिकतम ६ महीने होगी।

f) प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी: प्राधिकृत में, केंद्र देशभर में अनुसंधान और सामर्थ्य निर्माण अभ्यासों को कैरी आउट करने और विश्वसम्मत संगठनों और शैक्षिक संस्थानों के साथ संबंधित आता है। एनसीजीजी ने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और सिनर्जियों को प्राप्त करने के लिए १३ संस्थानों के साथ समझौता किया है, जिनमें से अब ११ संचालन में हैं।

एनसीजीजी अब नई संचयनों को साझेदारियों के साथ कर रहा है, जैसे कि आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम रांची, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ), इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (इन्सा), इन्वेस्ट इंडिया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई), और अन्य। इससे अनुसंधान क्षमता में वृद्धि होगी और एनसीजीजी की सहयोग के लिए उपयुक्त क्षेत्र में ज्ञान और विचारों का आसान आपसी अदला-बदली किया जाएगा। केंद्र आंतरराष्ट्रीय सहयोग और विकासशील देशों और उनके संगठनों के साथ भी प्राथमिकता देगा जो सार्वजनिक नीति और प्रशासन के क्षेत्र में ज्ञान और विचारों के संविदानित एवं संगठन में सख्त विचार एवं विचारों की स्मूद्धादी आपसी विनिमय के लिए काम कर रहे हैं।

g) सर्वोत्तम प्रथाओं के राष्ट्रीय रेपोजिटरी का विकास: एनसीजीजी एक सर्वोत्तम प्रथाओं के रेपोजिटरी के विकास पर काम करने की प्रस्तावना कर रहा है, जिसके लिए वेब-सिस्टम विकसित किया जाएगा ताकि लोग अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचार अपलोड कर सकें। एक टीम इन नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं की मूल्यांकन और समीक्षा करेगी और उन्हें स्केलिंग और प्रसार के लिए ज्ञान बैंक बनाएगी। नए प्लेटफॉर्म भी डुप्लिकेशन से बचाएंगे और देश के विभिन्न हिस्सों सहित अन्य देशों से सर्वोत्तम प्रथाओं को विस्तृत उपयोग के लिए स्रोत बनाएंगे।

h) बुनियादी ढांचा विकास: पिछले कुछ वर्षों से, एनसीजीजी विभिन्न क्षेत्रों में नीति मुद्दों, शासन, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, संचार, आउटरीच और साक्ष्यात्मक निर्णय लेने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। इसके अनुसार, एनसीजीजी नीति मुद्दों, शासन, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, संचार, आउटरीच और साक्ष्यात्मक निर्णय लेने के विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार और विविधीकरण कर रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य एनसीजीजी को एक वास्तव में विश्व-स्तरीय संस्थान के रूप में स्थापित करना है।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय के सहयोग सहित, एनसीजीजी अपनी क्षमता निर्माण कार्यक्रम को और देशों को शामिल करके महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित कर रहा है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और संगोष्ठियों को आयोजित करने की भी योजना बना रहा है। एनसीजीजी एक आईटी प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बना रहा है जो ई-प्रशासन परियोजनाओं के लिए समर्पित होगी। इसमें विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और राज्यों के साथ सहयोग करने के लिए पेशेवरों को लाना शामिल होगा। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति से सर्वोत्तम प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने वाला एक अनुकूल और तंगी-मुक्त वातावरण बनाना है। कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे नियम और विनियमों का तैयारी करना, उचित रिकॉर्ड-रखरखाव प्रणालियों का विकास, उपयुक्त कार्यालय स्थान और क्यूबिकल की प्रदान करना, और ई-प्रशासन

परियोजनाओं के लिए एक आईटी प्रयोगशाला स्थापित करना। इन प्रयासों और कई अन्य गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनसीजीजी अपने भौतिक अवसंरचना को बड़ा बना रहा है और केंद्रीय दिल्ली में स्थानांतरित हो रहा है, जहां इसे एक बड़ी कार्यबल तक आवासीय श्रमसंख्या को भी समर्थित किया जा सकता है।

- i) **वित्त:** डीएआरपीजी और वित्त मंत्रालय ने एनसीजीजी को 'विश्व-स्तरीय संस्थान' बनाने के विचार का बहुत समर्थन किया है। उपरोक्त सभी गतिविधियों को कार्यान्वयन करने के लिए, सरकार ने एनसीजीजी को ग्रांट-इन-एड में राशि को बढ़ाकर २०२२-२३ में ४.९५ करोड़ रुपये से २०२२-२३ में ११.५० करोड़ रुपये कर दिया है। वर्ष २०२३-२४ के लिए, एनसीजीजी को ग्रांट-इन-एड ३० करोड़ रुपये तक और बढ़ा दिया गया है।

एनसीजीजी खबरों में

एनसीजीजी भारत और विकसित देशों में सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाने और अच्छी शासन पहलों को बढ़ावा देने के लिए समाचार में रहा है, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में कुशलता और पारदर्शिता में वृद्धि हो। यहां कुछ तस्वीरें शामिल हैं।

mint

53rd Capacity Building programme of Bangladesh civil officials starts at NCGG

1 min read . Updated: 11 Oct 2022, 02:54 PM IST

NEWS 18

Sri Lankan President Asks India's Help With Policy Reforms, Governance, Public Service Delivery

BW BUSINESSWORLD

India To Train 1,000 Civil Servants Of Maldives

The capacity building programme for civil servants of developing countries aims to equip them with cutting edge knowledge, skills and fail to design and deliver effective public policy

INDIA TODAY

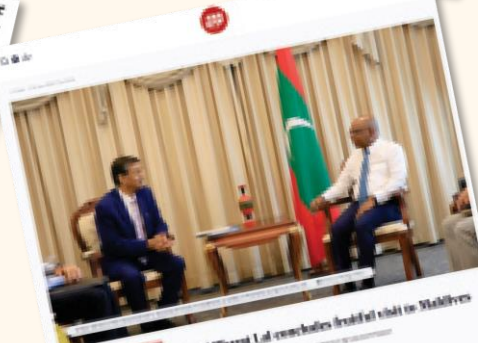
Focussing North-East, NCGG working to create pool of well-trained civil servants to address emerging challenges

In a first, officers from Arunachal Pradesh were trained at NCGG, both at Mussorie and New Delhi.

Business Standard

Centre creating ecosystem to benefit each of 140 crore Indians: NCGG chief

The Centre is creating an ecosystem where each of 140 crore Indians can take benefit of government policies, chief of National Centre for Good Governance (NCGG) Bharat Lal said on Sunday



NCGG's Director General Bharat Lal reaches Maldives for official visit

पड़ोसी पहले • हिमालयी समझौते के तहत विदेश मंत्रालय की पहल
गुड गवर्नेंस: मालदीव के 1000 अफसरों को ट्रेनिंग देगा भारत, 34 का प्रशिक्षण शुरू



भास्कर न्यून । नहीं मिली



आफन-विषय विषय लक्षित हा। अनेक महाने बोलबंदी के अधिकारीयो को भी प्रतिबन्ध दिश का चुनन हे।

इस प्रतिबन्ध काफेसक का उद्घाटन मेन्सल सेंटर फेस गुड कर्मस के मन्त्रिदेशक भास ताल न हे किन्तु अपसर पर उन्हेन सेशनशेल होने और तेली को सेवा में तराफवी होने का अवसरक पर जोर दिया। उन्हेन का भी कहा कि जेने से और बड़े जेने पर काम करना और सेवाओं के विचार को क्रियान्वित निवाहन में डिजिटल तकनीक का उपयोग करना निश्चित आवश्यक है क्योंकि तेल प्रोडश नहीं कर सकते। अब तेली को नकल तस्वीर हे।

भारत-मालदीव के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और पापुआ न्यूगिनी के तेल ताल भारत, मलदीव के 1000 प्रशासनिक अधिकारीयो को प्रशिक्षण देनेवा। इसके ताल 34 अधिकारीयो का दो माला का तेलीसवा प्रतिबन्ध संस्थान राष्ट्रीय तुलनात्मक संशोधन में प्रतिबन्ध शुरू हुआ। केन्द्र (एसीसीओ) में लोक प्रशासन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, लोकनीति और सुरक्षा, सूचना-ई-गवर्नेंस, तेलीय इलाकी में मान्य पालन प्रौद्योगिकी, तेलीय इलाकी, कृषि आर्थिक में समर्थन अन्वी प्रक्रिया, कृषि आर्थिक प्रक्रियाएँ, नवय मालात समुदाी को पालन, राष्ट्री विकास और प्रशासन में जेनस एवं

आकर-विचार विचार लब्धमान है। मैं
 पहले बंधनमोक्ष के अधिकारियों को भी
 जोर-शोर दिया कि मुझ से।
 इस प्रतिभवा कर्मकांड का उद्घाटन
 नेतृत्व में ही फीट फीट चलने के
 महानिर्देशक भाग लाने में लगे। इन
 अमर पर उन्होंने संकेतनाएँ
 और लोगों को लाने में उमरपति होने की
 अवसरकाय पर जोर दिया। उन्होंने यह
 भी कहा कि देखो मैं और बड़े फायदे पर
 काम करना और सेवाओं के विचार और
 विचारमय निष्कार में विचारित कर्मकांड का
 उद्घाटन करना निश्चित अत्यन्तक है क्योंकि
 लोग प्रतीति की लान सकते। अब लोगों की
 जलन लब्धमान है।

बांग्लादेश प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित



१०. यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गलती करे, तो वह अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करेगा।
 ११. यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गलती करे, तो वह अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करेगा।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[illegible]

**शासन
जित**

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की हुई बैठक

[illegible]

- हरियाणा सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से भी जानकारी
- विभिन्न ब्राह्मण समुदायों और समुदाय के बीच एक मान्यतापूर्ण समीक्षा: उपमुख्य

2000 1000 500 0

[illegible][illegible]

जिन्ना ने जलजुक्त खाद्य-पदार्थों को खाने से रोक दिया

Wiederholungsfragen

[illegible][illegible]

Scanned with CamScanner

महाराष्ट्र

१. प्रत्यक्ष : प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष
 २. अप्रत्यक्ष : अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
 ३. प्रत्यक्ष : प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष
 ४. अप्रत्यक्ष : अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
 ५. प्रत्यक्ष : प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष
 ६. अप्रत्यक्ष : अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
 ७. प्रत्यक्ष : प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष
 ८. अप्रत्यक्ष : अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
 ९. प्रत्यक्ष : प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष
 १०. अप्रत्यक्ष : अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष

है। प्रत्यक्ष सामान्य और सामाजिक सम्बन्धों में
हमारे लिए हमारे ही नए सामाजिक और सामाजिक
सम्बन्धों में सामान्य और सामाजिक सम्बन्धों में
हमारे ही नए सामाजिक और सामाजिक सम्बन्धों में
हमारे ही नए सामाजिक और सामाजिक सम्बन्धों में
हमारे ही नए सामाजिक और सामाजिक सम्बन्धों में

१. **संस्कृत भाषा** : संस्कृत भाषा हिन्दु धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक प्राचीन भाषा है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा बोली जाती है।
 २. **हिन्दु धर्म** : हिन्दु धर्म एक प्राचीन धर्म है, जो भारत में बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत धर्म है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।
 ३. **भारत** : भारत एक प्राचीन देश है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत देश है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।
 ४. **भारतीय संस्कृति** : भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत संस्कृति है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।
 ५. **भारतीय धर्म** : भारतीय धर्म एक प्राचीन धर्म है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत धर्म है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।
 ६. **भारतीय समाज** : भारतीय समाज एक प्राचीन समाज है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत समाज है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।
 ७. **भारतीय अर्थव्यवस्था** : भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्राचीन अर्थव्यवस्था है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत अर्थव्यवस्था है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।
 ८. **भारतीय राजनीति** : भारतीय राजनीति एक प्राचीन राजनीति है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत राजनीति है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।
 ९. **भारतीय विज्ञान** : भारतीय विज्ञान एक प्राचीन विज्ञान है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत विज्ञान है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।
 १०. **भारतीय कला** : भारतीय कला एक प्राचीन कला है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। यह एक बहुमत कला है, जो आज भी बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है।

1. **संज्ञा**
 2. **संख्या**
 3. **संज्ञा**
 4. **संख्या**
 5. **संज्ञा**
 6. **संख्या**
 7. **संज्ञा**
 8. **संख्या**
 9. **संज्ञा**
 10. **संख्या**

एनसीजीजी में प्रमुख वक्ता

विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) सत्रों में विभिन्न प्रख्यापकों ने अपनी उपस्थिति का सम्मान दिया है। यहां कुछ इवेंट्स की तस्वीरें हैं।



श्री एम. जे. अकबर, पूर्व मंत्री ऑफ स्टेट, विदेश मंत्रालय, मालदीव और जम्मू और कश्मीर के सिविल सेवकों के लिए संयुक्त वैदिक अवसान सत्र में



श्री हर्षवर्धन शृंगला, जी२० अध्यक्षी और पूर्व विदेश सचिव, मालदीव और जम्मू और कश्मीर के सिविल सेवकों के लिए संयुक्त वैदिक अवसान सत्र में



श्री एस. के. जयस्वाल, निदेशक और श्री प्रवीण सिन्हा, विशेष निदेशक, सीबीआई, बांग्लादेश, मालदीव और अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए संयुक्त वैदिक अवसान सत्र में



श्री विनय मोहन क्वात्रा, भारत के विदेश सचिव, मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए संयुक्त सत्र में



श्री शोम्बी शार्प, भारत के यूएन रहेने वाले समन्वयक, बांग्लादेश और अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए संयुक्त वैदिक अवसान सत्र में



श्री प्रवीण सिन्हा, विशेष निदेशक और श्री विनीत विनायक, संयुक्त निदेशक, सीबीआई, भ्रष्टाचार रोकथाम रणनीतियों और निगरानी प्रशासन पर एक सत्र में



श्री संजय भट्टाचार्य, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय, डिजिटल शासन पर एक सत्र में



श्री दिनेश दासा, पूर्व अध्यक्ष, गुजरात लोक सेवा आयोग, नीति हस्तक्षेपों पर एक सत्र में



डॉ. बलराम भार्गव, प्रोफेसर और हेड कार्डियोलॉजी, चीफ सीटी सेंटर, एम्स, नई दिल्ली, बांग्लादेश के सिविल सेवकों को कोविड-१९ महामारी प्रबंधन पर बता रहे हैं।

एनसीजीजी टीम

श्री वी. श्रीनिवास

पूर्व महानिदेशक, एनसीजीजी (२३ सितंबर, २०२२ तक)



उन्होंने १९८९ में २२ वर्ष की आयु में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए थे और ३२ वर्षों की प्रतिष्ठित सेवा का अनुभव है। उन्होंने एम्स में उपनिदेशक (प्रशासन) के रूप में सेवा की, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक, भारत सरकार के मंत्रालय में संयुक्त सचिव (वस्त्र मंत्रालय), भारत सरकार के मंत्रालय में संयुक्त सचिव (संस्कृति मंत्रालय), राजस्थान के सरकारी वित्त और योजना विभाग के सचिव, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार (२००३-२००६), भारत के वित्त मंत्री के निजी सचिव और भारतीय विदेश मंत्री के निजी सचिव के रूप में सेवा की है। उन्होंने सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक प्रशासन पर १६२ लेख/पत्रिकाएं लिखी हैं और ६३ व्याख्यान दिए हैं। वह एक वरिष्ठ नीति निर्माता, एक शिक्षाविद और एक संस्थान निर्माता हैं।

श्री भारत लाल

महानिदेशक, एनसीजीजी (२६ सितंबर, २०२२ से अब तक)



श्री भारत लाल, जुलाई, १९८८ में सिविल सेवा में शामिल हुए थे और गुजरात और केंद्र सरकार के साथ विस्तृत रूप से काम किया। सितंबर, २०२२ में उन्होंने राष्ट्रीय सरकार के लोकपाल के सचिव के रूप में काम किया था। इससे पहले, उन्होंने 'जल जीवन मिशन' के संस्थापक मिशन निदेशक के रूप में काम किया था, जो अगस्त, २०१९ में शुरू किए गए एक प्रमुख कार्यक्रम था, जिसका लक्ष्य २०२४ तक देश के हर घर और सार्वजनिक संस्थान को साफ नल से जल प्रदान करना था। उन्होंने भारत के तब से बहुत जल्दी से अपने करियर में जल संरक्षण, गिरी हुई भूमि के पर्यावरणीय संवर्धन और गरीबी निवारण पर काम करना शुरू कर दिया था। श्री भारत लाल को उनकी बॉक्स से बाहर सोचने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए समाधान ढूंढने के लिए जाना जाता है।

श्रीमती पूनम सिंह

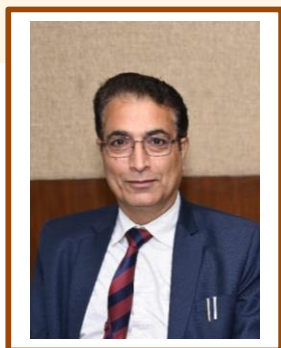
एसोसिएट प्रोफेसर



वह २०१४ से एनसीजीजी के साथ काम कर रही हैं। पहले, उन्होंने १९९०-९४ में गया कॉलेज, गया (मगध विश्वविद्यालय, बिहार) में एक लेक्चरर के रूप में काम किया था, १९९८ से सितंबर, २००५ तक बिहार शिक्षा परियोजना, डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पर काम किया था और डीपीईपी और एसएसए के कार्यान्वयन में थीं। उन्होंने अक्टूबर, २००५ से २०१४ तक पूर्व एनआईएआर, एलबीएसएनए के साथ काम किया था। उन्होंने शासन मुद्दों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसएसए के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, वार्षिक कार्य योजना और बजट से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर समन्वय किया है। वह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के योजना मंजूरी बोर्ड (पीएबी) के सदस्य थीं।

डॉ. ए. पी. सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर



डॉ. सिंह के पास प्रबंधन, शासन, प्रशासन और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान करने और प्रशिक्षण संगठन को संचालित करने का अनुभव है। आँकड़ा विश्लेषण के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता है, जिसके लिए उन्होंने सांख्यिकी में एम. फिल और पीएचडी हासिल की है। उन्होंने भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में कई काम प्रकाशित किए हैं और उनके नाम से किताबें भी हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के विभिन्न शोध अध्ययनों को सफलतापूर्वक पूरा करने और प्रकाशित करने में सहयोग किया है। उन्होंने विभिन्न देशों के सिविल सेवकों के लिए ७५ अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक समन्वय किया है और लोक सभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवक, कोयला इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संयोजित किया है।

डॉ. बी. एस. बिष्ट

एसोसिएट प्रोफेसर



जीओग्राफी में एमए और पीएचडी धारण करने वाले डॉ. बी. एस. बिष्ट के पास अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण में २० से अधिक वर्षों का अनुभव है। उन्होंने जीबीपीआईएचडी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का संगठन, भारत सरकार) में एक अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में काम किया है और उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में एक शिक्षक के रूप में भी काम किया है। उन्होंने

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में ३० से अधिक अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन किया है और 'ग्रामीण भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य: समस्या और प्रबंधन विकल्प' नामक तीन पुस्तकों का संपादन किया है, जिनमें श्री आलोक कुमार, आईएएस पूर्व उपनिदेशक, (एलबीएसएनए), 'भारत में जल और स्वच्छता पर विकासात्मक शासन' श्री कुश वर्मा, आईएएस, पूर्व महानिदेशक, एनसीजी और डॉ. एडेन क्रोनिन, मुख्य जल और स्वच्छता, यूनिसेफ, इंडोनेशिया और 'एक महामारी में अच्छा शासन अभ्यास' श्री वी. श्रीनिवास, आईएएस, सचिव, डीएआरपीजी और पूर्व महानिदेशक, एनसीजी और प्रोफेसर पूनम सिंह से एनसीजीजी। डॉ. बिष्ट ने देश भर में जल और स्वच्छता, सार्वजनिक नीति और शासन और प्रगत नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सफलतापूर्वक ९० क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

डॉ. यशु शर्मा

वित्त अधिकारी (अप्रैल, २०२३ से अब तक)



डॉ. यशु शर्मा ने २०१५ में भारतीय सिविल लेखा सेवा में शामिल हुए। अपने करियर के दौरान, उन्होंने सरकार के अनेक प्रतिष्ठित पदों का कार्यभार संभाला है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय में लेखा नियंत्रक सहायक के रूप में शुरुआत की और बाद में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में लेखा नियंत्रक के उपनियंत्रक के रूप में सेवा की। फिर उन्होंने वित्त मंत्रालय के लेखा महानिदेशक कार्यालय में लेखा महानिदेशक सहायक के पद का कार्य संभाला। वर्तमान में, वह कार्य मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के उपनियंत्रक के रूप में सेवा कर रहे हैं, जहां उन्हें राष्ट्रीय सरकारी ग्रामीण शासन केंद्र (एनसीजीजी) के लिए वित्त अधिकारी का जिम्मा भी सौंपा गया है।

डॉ. शर्मा के पास सरकारी बजट, भुगतान, लेखा और आंतरिक महानिरीक्षण में विस्तृत विशेषज्ञता है। उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में सीधी लाभ भुगतान (डीबीटी) भुगतान, जोखिम पर आधारित आंतरिक महानिरीक्षण, और डेटा विश्लेषण शामिल हैं। विशेष रूप से, उन्हें कंबोडिया के अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मिशन का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। नागरिक सेवा के पाठ्यक्रम के अलावा, डॉ. शर्मा एक चिकित्सा स्नातक हैं और उन्हें एमबीबीएस डिग्री से सम्मानित किया गया है और उन्हें पांच सोने के पदकों से सम्मानित किया गया है।

डॉ. गजला हसन

असिस्टेंट प्रोफेसर



डॉ। गजाला हसन, २००५ से राष्ट्रीय सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में सहायक प्रोफेसर हैं, जमिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से वे कॉमर्स में मास्टर्स और पीएचडी रखती हैं। वे कॉमर्स में विशेषज्ञता रखती हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण और प्रबंधन विकास में योगदान देती हैं। डॉ। हसन, एलबीएसएनए से प्रमाणित प्रशिक्षक हैं। डॉ। हसन, कोविड-१९ के दौरान प्रकाशित 'एक महामारी में अच्छे

गवर्नेस अभ्यास' जैसे प्रख्यापनीय शैक्षणिक योगदान के साथ, शोध, प्रशिक्षण और कार्यक्रम समन्वय में बहुमुखी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करती हैं। उनका अच्छे गवर्नेस अभ्यास को आगे बढ़ाने का समर्पण उन्हें एनसीजी के लिए एक मूल्यवान संपदा बनाता है और सार्वजनिक नीति और शासन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाता है।

डॉ. संजीव शर्मा

रिसर्च एसोसिएट



डॉ. संजीव शर्मा के पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में विस्तृत अनुभव है और वह वर्षों से लोक सभा सचिवालय, राज्य नागरिक सेवा अधिकारियों और कोयला इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों जैसी प्रतिष्ठित संगठनों के लिए घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक समन्वित कर चुके हैं। उन्होंने जर्नल्स और बुक्स में अनुसंधान लेख भी प्रकाशित किए हैं। उन्हें अंकगणितीय और सांख्यिकीय विश्लेषण में कुशलता है। वह प्राग्या इंटरनेशनल संगठन के लिए एक विजिटिंग फैकल्टी भी थे। वह शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययनों को भी समन्वित कर चुके हैं। उन्होंने एम.ए. (सोशलॉजी), एम.ए. (अंग्रेजी) और डॉ. (सोशलॉजी) डिग्री हासिल की है। वह कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी कर चुके हैं, इसके अलावा उन्होंने एलबीएसएनएए, मसूरी से डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस) कोर्स भी पूरा किया है, साथ ही ग्राफिक एरा, देहरादून से डीटीपी और ऑटो कैड के सर्टिफिकेट कोर्स किया है।

डॉ. मुकेश के भंडारी

रिसर्च एसोसिएट



डॉ. मुकेश के. भंडारी ने सफलतापूर्वक ७५ अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय किया है और नेता सेवकों के लिए लोक सभा सचिवालय और राज्य नेता सेवकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन्होंने प्रज्ञा के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 'स्थानीय लोगों के अधिकार' पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया। इसके अलावा, उन्होंने २००२ में लोकनीति की विधानसभा चुनाव अध्ययन के लिए क्षेत्र पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। डॉ. भंडारी के पास एच.पी. विश्वविद्यालय, शिमला से राजनीति विज्ञान में एम.ए. है, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट है, और सभी इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बॉम्बे से स्थानीय स्वायत्त सरकार में डिप्लोमा पूरा किया है। उन्होंने लल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षक कौशल (डीटीएस) पाठ्यक्रम भी लल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी से पूरा किया है।

अनुबंध - I

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के शासी निकाय के सदस्य

१.	कैबिनेट सचिव	अध्यक्ष
२.	सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	उपाध्यक्ष
३.	सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
४.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
५.	सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
६.	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
७.	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
८.	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
९.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
१०.	सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य
११.	शिक्षाविद/प्रख्यात प्रशासक/विशेषज्ञ/प्रतिष्ठित नवप्रवर्तक/ प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख	सदस्य (५)
१२.	महानिदेशक, एन.सी.जी.जी.	सदस्य-सचिव

अनुबंध - II

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की प्रबंधन समिति के सदस्य

१.	सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	अध्यक्ष
२.	सचिव समन्वय, कैबिनेट सचिवालय	सदस्य
३.	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह)	सदस्य
सचिव या उनके नामिती जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों		
४.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
५.	ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
६.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
७.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
८.	उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
९.	आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
१०.	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
११.	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य
१२.	महानिदेशक, एन.सी.जी.जी.	सदस्य-सचिव

अनुबंध - III

टेबल: मालदीव के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का विवरण

क्रम संख्या	अवधि	बैच	प्रतिभागियों की संख्या
१.	९ मई - २० मई, २०२२	११ th	४०
२.	३० मई - ३ जून, २०२२	१२ th	३९
३.	१३ जून - १७ जून, २०२२	अध्ययन यात्रा	११
४.	२० जून - १ जुलाई, २०२२	१३ th	३७
५.	२५ जुलाई - २९ जुलाई, २०२२	१४ th	२५
६.	२२ अगस्त - २ सितंबर, २०२२	१५ th	३६
७.	१२ सितंबर - २३ सितंबर, २०२२	१६ th	३७
८.	३१ अक्टूबर - ११ नवंबर, २०२२	१७ th	३४
९.	५ दिसंबर - ९ दिसंबर, २०२२	१८ th	२३
१०.	१२ दिसंबर - २३ दिसंबर, २०२२	१९ th	२७
११.	९ जनवरी - २० जनवरी, २०२३	२० th	२७
१२.	१३ फरवरी - १७ फरवरी, २०२३	२१ st	२५

अनुबंध - IV

टेबल: बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का विवरण

क्रम संख्या	अवधि	बैच	प्रतिभागियों की संख्या
१.	२२ अगस्त २०२२ - २ सितंबर २०२२	५२ nd	३९
२.	१० अक्टूबर २०२२ - २१ अक्टूबर २०२२	५३ rd	४०
३.	२१ नवंबर २०२२ - २ दिसम्बर २०२२	५४ th	३७
४.	१२ दिसम्बर २०२२ - २३ दिसम्बर २०२२	५५ th	३९
५.	९ जनवरी २०२३ - २० जनवरी २०२३	५६ th	३९
६.	२७ फरवरी २०२३ - १० मार्च २०२३	५७ th	४०

अनुबंध - V

टेबल: जम्मू और कश्मीर के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

क्रम संख्या	अवधि	बैच	प्रतिभागियों की संख्या
१.	२८ नवम्बर - ९ दिसम्बर, २०२२	४ th	२९
२.	६ फरवरी - १७ फरवरी, २०२३	५ th	३८

अनुबंध - VI

टेबल: अरुणाचल प्रदेश के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

क्रम संख्या	अवधि	बैच	प्रतिभागियों की संख्या
१.	९ जनवरी - २० जनवरी, २०२३	१ st	२२
२.	२७ फरवरी - १० मार्च, २०२३	२ nd	२९

अनुबंध - VII

टेबल: सुखम प्रशासन वेबिनार श्रृंखला के विवरण

क्रम संख्या	श्रेणियाँ/ प्रयास	तिथि
१.	सेवा प्रदान में सुधार - सकाला और ई-सेवा	२८ अप्रैल, २०२२
२.	सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम (गुजरात) और दवाइयों की कीमतों को कम करना (राजस्थान)	२७ मई, २०२२
३.	लक्ष्यपूर्ण जिलों कार्यक्रम	२४ जून, २०२२
४.	सार्वजनिक शिकायतों का समाधान	२९ जुलाई, २०२२
५.	पर्यावरण	२६ अगस्त, २०२२
६.	सार्वजनिक सेवा प्रदान	३० सितंबर, २०२२
७.	स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जन भागीदारी	२८ अक्टूबर, २०२२
८.	नवाचार - केंद्र और राज्य	२५ नवम्बर, २०२२
९.	हर घर जल योजना	३० दिसम्बर, २०२२
१०.	नवाचार - जिला स्तर	२७ जनवरी, २०२३
११.	लक्ष्यपूर्ण जिलों कार्यक्रम	२४ फरवरी, २०२३
१२.	नमामि गंगे	३१ मार्च, २०२३

नोट: _____

एनसीजीजी के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अंकशिक्षा





सत्यमेव जयते
Government of India

NCGG

National Centre for Good Governance
The Torch Bearers of Good Governance

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

ब्लॉक IV, 4वाँ मंजिल, पुराना जेएनयू कैम्पस,
नई मेहरौली मार्ग, नई दिल्ली - 110 067

Tel: +91-011-2616 9136 - 39

ईमेल: ncgg-dopt@nic.in



www.ncgg.org.in



[NCGG_GoI](https://twitter.com/NCGG_GoI)



[NCGG India](https://www.facebook.com/NCGGIndia)